

(ख) क्या सरकार का विचार प्रबन्धक-मंडलों को अधिक कुशल और सक्रिय बनाने की दृष्टि से इनमें सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त उपभोक्ता, कर्मचारी और जनता के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के प्रश्न पर गौर करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक, और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) से (घ). सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों के निदेशक बोर्ड में सामान्यतः कम्पनी के कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक शामिल किए जाते हैं। गैर-सरकारी निदेशकों का चयन करते समय इस बात का उचित ध्यान रखा जाता है कि कम्पनी के लिए उपयोगी विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।

Production and Requirement of Synthetic Rubber

*953. SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) the quantity of synthetic rubber produced in the country and total requirement of the same at present;

(b) whether synthetic rubber is being imported; and

(c) if so, the countries from which the imports are made?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) The quantity of synthetic rubber produced in the country during 1978-79 and 1979-80 was 28,578 tonnes and 30,320 tonnes respectively. The estimated demand for synthetic rubber for 1980-81 is 50,000 tonnes.

(b) Yes, Sir.

(c) Imports are made from Belgium, Canada, France, West Germany, Japan, U.K. U.S.A. and U.S.S.R.

नर्मदा नहर से जल प्राप्त करने वाले राजस्थान के क्षेत्रों के नाम

*955. श्री बृद्धि चन्द्र जैन : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नर्मदा नहर से राजस्थान के किन-किन क्षेत्रों का तथा कितना-कितना क्यूसेक पानी मिलेगा तथा उसमें कितने क्षेत्र को सिंचाई हो सकेगी;

(ख) उक्त नहर के निर्माण हेतु वर्ष 1980-81 के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा 1980 से 1985 तक कितनी राशि के लिए जानें का विचार है और इस निधि में कितना कार्य किया जायेगा; और

(ग) उक्त नहर का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और उस पर कितना रुच आयेंगा?

सिंचाई मंत्री (श्री कंदार पाण्डेय):

(क) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अन्तिम निर्णय के अनुसार राजस्थान को 0.5 मिलियन एकड़ फुट जल आवंटित किया गया है। राजस्थान को यह जल, गुजरात द्वारा गुजरात-राजस्थान सीमा तक बनाई जाने वाली नवागांव नहर के जिए दिया जाएगा। राजस्थान सीमा पर इस नहर की क्षमता 2500 क्यूसेक होगी। राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिलों का कामान क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला कृषि योग्य क्षेत्र 148600 हेक्टेयर होगा।

(ख) राजस्थान सरकार ने वर्ष 1980-81 के लिए 20 लाख रुपये के और 1980-85 की योजना अवधि के लिए 20 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। राज्य द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय विस्तृत निर्माण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राजस्थान में नहर प्रणाली